

10

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017-18

I/मिगरानी/छिन्दवाड़ा/भू-रा/2017/6376

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

: संस्कृत पुस्तकोन्निति विद्यापीठ (समिति) सभा द्वारा सरवराकार/सचिव- स्वामी नरेन्द्र ब्रम्हचारी पिता श्री बद्री प्रसाद तिवारी, उम्र करीब 63 वर्ष, शिष्य संत श्री आशाराम संस्कृत पुस्तकोन्निति विद्यापीठ (समिति) द्वारा मुख्त्यारआम श्री रामकश्यप पिता स्व. खिचडू कश्यप, निवासी- ग्राम खजरी, तह. व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

477



विरुद्ध

गैर-पुनरीक्षणकर्ता
/अनावेदक

: म.प्र. शासन, द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (व्यपवर्तन अधिकारी) छिन्दवाड़ा, तह. व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक- 526/बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 एवं विचारण न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 83/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2015 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों के साथ प्रस्तुत है:-

पुनरीक्षण के तथ्य


1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व के मालिक काबिज हक

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/छिंदवाड़ा/भूरा./2017/6376

जिला - छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/1/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निग0 आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 526/बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनांक 16-9-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 16-9-16 को पारित किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 6-12-17 को अर्थात् 14 माह विलंब से पेश की गई है । विलंब के संबंध में ना तो अवधि विधान की धारा 5 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है और ना ही तर्कों में इस प्रकार का कोई निवेदन किया गया है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि बाह्य होने के कारण इसी स्तर पर निरस्त की जाती है ।</p> <p>3/ पक्षकार सूचित हों ।</p>	<p> प्रशा0 सदस्य</p>